







# पूरब और पश्चिम में बदलता शक्ति संतुलन

टीएन नाइनन

पश्चिमी जगत और बाकी की दुनिया के बीच बढ़ते जा रहे मुकाबले में, अब यह स्पष्ट है कि भले पश्चिम के हाथ में अभी भी अधिक ताकत हो किंतु वह कमजोर पड़ता जा रहा है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, अमेरिका की नौसेना का रुख अब 'दबदबे' वाली भूमिका से बदलकर 'प्रतिरोधक' में तब्दील हो गया है। आर्थिक परिधि में भी, अमेरिका का रवेया आक्रामकता से (तकनीक पर प्रतिबंध, व्यापार पर रोक और आर्थिक नाकाबंदी) से बदलकर रक्षात्मक (अमेरिकी बाजार में आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाना) हो गया है। और यूक्रेन को मिला पश्चिमी समर्थन रूस को नहीं रोक पाया। माओ ने शायद समय से पहले ही घोषणा कर दी थी - 'एक दिन पूरब की हवा पश्चिमी वायुमंडल पर छा जाएगी।' और अब यह होना शुरू हो गया है। सालों तक, पश्चिमी विश्लेषकों और पत्रकारों ने चीन और रूस को पढ़ने में चूक की है। रूस को तो वे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर मानते रहे और व्लादिमीर पुतिन को राजनीतिक रूप से चुनौती देने लायक समझते रहे। दशकों पहले चीन के भरभराकर ढहने की भविष्यवाणी भी की गई थी और हाल में उसे समस्याओं से घिरा बताते रहे। फिर भी रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों का अप्रत्याशित रूप से डटकर सामना किया, यूक्रेन में उसका हाथ ऊपर है और पुतिन ने एक बार फिर चुनाव में कार्यकाल अर्जित किया। इसी दौरान, तुलनात्मक आय स्तर वाली अर्थव्यवस्थाओं में चीन सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिकी बना रहा।

अमेरिका द्वारा चीन से आयातित कुछ वस्तुओं पर लगाए करों में तीखी वृद्धि पूर्ण-स्तरीय व्यापार युद्ध को चालू करने का बायस नहीं बन पाई क्योंकि इसके निशाने पर वह वस्तुएं हैं जिनकी बिना चीन अमेरिका में ज्यादा नहीं करता। इसलिए यह प्रतीकात्मक कदम मुख्यतः राष्ट्रपति बाइडेन के घरेलू राजनीतिक हितों को साधने की गरज है। भले ही चीन निशाने पर ली गई इन वस्तुओं में बहुतेतों का बड़ा उत्पादक है लेकिन वह अपने माल के लिए अन्य मंडियों तलाश लेगा। बल्कि यह अमेरिकी आयातक हैं जिनके पास कुछ वस्तुओं को मंगवाने के वैकल्पिक स्रोत नहीं हैं, फिर चीन तीसरे देश में लगाए अपने कारखानों की मार्फत इन वस्तुओं को अमेरिका पहुंचा सकता है। इसी बीच, अमेरिकी उपभोक्ता महंगा माल खरीदने के लिए विवश रहेंगे। इस प्रकार के रक्षात्मक खेल (जो कि भारी सस्मिडी देकर अमेरिकी उत्पादकता को फिर से जिंदा करने का दूसरा पहलू है) पहले अपनाए गए आक्रामक रुख के विपरीत है। उम्मीद यह थी कि उक्त आक्रामक कदम अमेरिका के दुश्मनों की घेराबंदी करेंगे। कोई शक नहीं कि प्रतिबंधों से चुभन होती है (जैसा कि हमेशा प्रतिबंधों के मामले में होता है) लेकिन इसका असर आंशिक रहा। रूस ने अपने तेल एवं गैस के लिए नए ग्राहक ढूंढ लिए जबकि पूरबी यूरोप को अपनी ऊर्जा जरूरतों के अहम स्रोतों के तौर पर सस्ती रूसी गैस से हाथ धोना पड़ा, जिससे जर्मनी जैसे मुल्क की भी आर्थिकी हिल गई। इसी बीच, रूसी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होती गई। रूस और चीन, दोनों ने



भुगतान का नया तरीका विकसित कर लिया और इससे डॉलर पर निर्भरता न रही (अब इनका 95 फीसदी व्यापार स्थानीय मुद्रा में हो रहा है), यहां तक कि एक अलग 'स्विफ्ट' नामक बैंकिंग संचार प्रणाली भी विकसित कर ली है। रूस के रिजर्व खजाने में आज डॉलर के मुकाबले चीनी मुद्रा रेनमीबिस का भंडार अधिक है। उधर चीन अपना धन सोने में बदल रहा है, जिसके लिए पिछले 18 महीनों में भारी स्वर्ण खरीदारी की है। भले ही पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना का वर्तमान 2,250 टन सोना कुल रिजर्व भंडार का 5 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन आज तक की तारीख तक यह मात्रा सबसे अधिक है। जहां तक तकनीक का मामला है, किसी अन्य देश के मुकाबले चीन इस क्षेत्र में अधिक तेजी से तरक्की कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और लिथियम बैटरी से चालित वाहन या अन्य उपकरणों में प्रयुक्त इस विशेष जरूरत की आपूर्ति के मामले में चीन बाकी देशों से कहीं आगे है और कुछ मंडियों में अपनी धाक बना चुका है। अब वह इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफ साइंस और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नई खोज के

बूते लंबी छलांग लगाने में सक्षम है। उदाहरणार्थ, हुआवे ने हाल ही में 7 नैनोमीटर वाली चिप से युक्त अपने नए स्मार्ट फोन से पश्चिमी जगत को चौंका डाला और अब 5 नैनोमीटर वाली चिप तैयार करने पर काम चल रहा है। उसने अगले साल तक चिप निर्माण में 75 फीसदी आत्मनिर्भरता पाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच, पश्चिमी देशों की दवा उत्पादक कंपनियों ने भी शंघाई के निकट सुज्हेऊ में बायो-वे जैसे विशालकाय नवोन्मेषण केंद्र में बायोफार्मा और लाइफ साइंस में हो रही तरक्की के बूते चीन की उभरती सरदारी को मान्यता दी है। रक्षा क्षेत्र में, चीन अपना चौथा विमानवाहक पोत बना रहा है जो शायद परमाणु ऊर्जा चालित होगा, यह एक अन्य तकनीक बाधा लांघने का प्रतीक है। सच्चाई यह है कि चीन के तकनीक विकास रथ को रोकने में बहुत देर हो चुकी है। रक्षा मोर्चे पर, पश्चिमी टिप्पणीकारों को इस संभावित उलटफेर की चिंता सता रही है कि कहीं रूस यूक्रेन में अपने मंसूवों में सफल हो गया तो आगे बाकी अर्ध-बर्बाद देश को न कब्जा ले। यदि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी

दरअसल, मोहम्मद मोखबर एक उच्च शिक्षित तथा क्रांति के विचार पोषक रहे हैं। उन्हें आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। ऐसे वक्त में जब परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की वजह से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगे हैं तो मोहम्मद मोखबर ने ईरानी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये भरसक प्रयास किये हैं। ईरान के खुजेस्तान प्रांत के देजफुल शहर में 1955 में जन्मे मोहम्मद मोखबर देजफुल को उपनाम उनके शहर के नाम पर ही मिला है। गंभीर धार्मिक रुझान वाले परिवार में उनके पिता इस्लामिक उपदेशक की भूमिका में भी रहे हैं। अपने शहर में आरंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद वे उच्चशिक्षा के लिये अहवाज गए। बताते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी के साथ ही प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री भी हासिल की। बाद में मैनेजमेंट व आर्थिक विकास में डॉक्टरेट भी की। ईरानी मीडिया के अनुसार मोहम्मद मोखबर ने बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून में पीएचडी भी हासिल की। कालांतर में वे इस्लामिक क्रांति से जुड़े वैचारिक संगठनों से जुड़े रहे। जिसमें तत्कालीन सरकार के विरुद्ध सक्रिय मंसूखन ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे। फिर खुजेस्तान में इस्लामिक रिपब्लिकन गाईस कोर में खासे एक्टिव रहे। उनकी सक्रियता ईरान-इराक युद्ध के दौरान भी रही। युद्ध के बाद वे कई बड़ी दूरसंचार कंपनियों में शीर्ष पदों पर रहे। सीमित अंतराल के लिये खुजेस्तान के डिप्टी गवर्नर की भूमिका भी रहीं। आर्थिक व प्रबंधन में गहरी पकड़ के चलते मोहम्मद मोखबर को सिना बैंक व ईरान सेल कंसोर्टियम में निदेशक मंडल जैसे बड़े पद मिले।

## संकट में ईरान के रहबर बने मोखबर

अरुण वैथानी

ईरान फिलहाल बड़े नेतृत्व व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यूं तो पहले से ही यह इस्लामिक देश अमेरिका और इस्राइल के निशाने पर रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिये सख्त अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों से बचते-बचाते ईरान जैसे-तैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश ही कर रहा था। मगर 20 मई के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी व विदेश मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौत, इस देश के लिये वज्रपात जैसी है। ऐसे में कार्यपालिका प्रमुख के रिक्त पद को भरना तात्कालिक चुनौती थी। ईरानी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विधिवत चुनाव होने तक उप-राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर देजफुली को ही राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल, ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद प्रधानमंत्री पद खत्म कर दिया गया था। फिर चुनाव हुआ राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति का मनोनयन करता रहा है। इस पद पर बैठे व्यक्ति लगभग प्रधानमंत्री जैसे कार्यपालिका के दायित्वों को निभाता है। उपराष्ट्रपति को शासन प्रमुख के निधन के बाद राष्ट्रपति को तमाम शक्तियां व दायित्व केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद मिल जाते हैं। ईरानी संविधान के अनुसार पचास दिन के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए।

दरअसल, मोहम्मद मोखबर एक उच्च शिक्षित तथा क्रांति के विचार पोषक रहे हैं। उन्हें आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। ऐसे वक्त में जब परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की वजह से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगे हैं तो मोहम्मद मोखबर ने ईरानी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये भरसक प्रयास किये हैं। ईरान के खुजेस्तान प्रांत के देजफुल शहर में 1955 में जन्मे मोहम्मद मोखबर देजफुल को उपनाम उनके शहर के नाम पर ही मिला है। गंभीर धार्मिक रुझान वाले परिवार में उनके पिता इस्लामिक उपदेशक की भूमिका में भी रहे हैं। अपने शहर में आरंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद वे उच्चशिक्षा के लिये अहवाज गए। बताते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी के साथ ही प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री भी हासिल की। बाद में मैनेजमेंट व आर्थिक विकास में डॉक्टरेट भी की। ईरानी मीडिया के अनुसार मोहम्मद मोखबर ने बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून में पीएचडी भी हासिल की। कालांतर में वे इस्लामिक क्रांति से जुड़े वैचारिक संगठनों से जुड़े रहे। जिसमें तत्कालीन सरकार के विरुद्ध सक्रिय मंसूखन ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे। फिर खुजेस्तान में इस्लामिक रिपब्लिकन गाईस कोर में खासे एक्टिव रहे। उनकी सक्रियता ईरान-इराक युद्ध के दौरान भी रही। युद्ध के बाद वे कई बड़ी दूरसंचार कंपनियों में शीर्ष पदों पर रहे। सीमित अंतराल के लिये खुजेस्तान के डिप्टी गवर्नर की भूमिका भी रही। आर्थिक व प्रबंधन में गहरी पकड़ के चलते मोहम्मद मोखबर को सिना बैंक व ईरान सेल कंसोर्टियम में निदेशक मंडल जैसे बड़े पद मिले। कालांतर में इस्लामिक गणराज्य की आर्थिकी रोड़ कहे जाने वाली संस्था 'फरमान इमाम' के मुख्यालय के प्रमुख की नियुक्ति के रूप में बड़ी सफलता पायी। दरअसल, 'फरमान इमाम' की स्थापना इस्लामिक क्रांति के सूत्रधार आयतुल्लाह खुमैनी की रणनीति के तहत हुई थी। इस संस्था और मोहम्मद मोखबर के कद का पता इस बात से पता चलता है कि कुछ साल पहले अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध लगाए थे। दरअसल, इस संस्था के कब्जे में इस्लामिक क्रांति के बाद जब अरबों की



संपत्ति है। जो सीधे ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अयातुल्लाह खामेनई के सुपरविजन में संचालित होती है। इस संस्था की अकूत संपदा की किसी ईरानी विभाग द्वारा निगरानी नहीं हो सकती है और संस्था का दखल कई महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में है। उल्लेखनीय है कि मोखबर डेढ़ दशक तक फरमान इमाम कार्यकारी अधिकारी रहे। दरअसल, ईरान के सुप्रीम नेता से करीबी संबंध और आर्थिक मामलों में गहरी पकड़ के चलते मोखबर ईरान के उपराष्ट्रपति बने थे। उन्होंने तमाम कट्टरपंथी नेताओं को मात देकर इस पद को हासिल किया था। वे जहां एक ओर सर्वोच्च धर्मगुरु अयातुल्लाह खामेनई के विश्वासपात्र रहे वहीं दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के भी भरोसेमंद रहे हैं। दरअसल, ईरानी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, यह पद जनता द्वारा चयनित नहीं होता। यद्यपि वे पद के पीछे से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों की सफलता को लेकर कई तरह के किंतु-परंतु होते रहे हैं। सवाल फरमान इमाम की आर्थिक नीतियों व काम करने के तौर-तरीकों तथा दर्जनों कंपनियों की मिलिक्यत

को लेकर भी उठते रहे हैं। संस्था सेवा कार्यों के लिये बरकत फाउंडेशन तथा नॉलेज फाउंडेशन भी चलाती है। दरअसल, मोखबर तब भी सुर्खियों में आए थे जब कोरोना महामारी के दौर में बरकत फाउंडेशन के तत्वावधान में ईरानी वैक्सीन प्रोजेक्ट को सिर्रे चढ़ाने के प्रयास हुए थे। इन प्रभावशाली व बड़ी संस्थाओं में निर्णायक भूमिका के साथ ही वैक्सीन ने उन्हें देश में नायकत्व प्रदान किया। ईरानी सर्वोच्च धार्मिक नेता की सहमति से चली योजना को लेकर कई किंतु-परंतु भी सामने आए। मोखबर ने अपनी बेटी को पहली वैक्सीन लगाकर देश के लोगों का भरोसा हासिल करने का प्रयास किया। दरअसल, मोहम्मद मोखबर ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों से उपजे संकट से देश को बाहर निकालने का सतत प्रयास किया। कालांतर में उनके योगदान व अनुभव के चलते ही उन्हें रेंजिस्टर्ड इकॉनमी का सर्वेसर्वा बनाया गया। वहीं ईरानी सत्ता के सूत्रधारों के साथ बेहतर रिश्तों के चलते वे पद के पीछे के खेल के मंजे खिलाड़ी भी माने जाते हैं। बहरहाल, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उन्हें ईरान में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला है।

## विचार

## एक चाल का तानाशाह

राजेंद्र शर्मा

गतांक से आगे...

पहली बात तो यह कि मोदी कोई पहले प्रधानमंत्री तो हैं नहीं, जो संसद में हों और जिनकी संसद के प्रति जवाबदेही बनती हो। हरेक प्रधानमंत्री को, संसद के किसी न किसी सदक का सदस्य होना ही होता है। फिर भी, मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने दस साल में एक भी खुली प्रेस कान्फ्रेंस का सामना नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि संसद में सवालों के जवाब देने का प्रधानमंत्री मोदी का रिकार्ड, पत्रकारों के सवालों का सामना करने के उनके रिकार्ड जितना ही खराब है। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दस साल में नरेंद्र मोदी ने संसद में भी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने संसद में, खास-खास सत्रों में, खास-खास बहसों के जवाब के नाम पर, अपने मन की बात भर की है, वना उनका रिकार्ड संसद से ज्यादातर समय गायब रहने का और उसकी चर्चाओं में हिस्सा लेने से बचने का ही रहा है। स्वतंत्र प्रेस के जरिए और जाहिर है कि संसद के जरिए भी, जनता के सामने जवाबदेही से ही प्रधानमंत्री मोदी के इस तरह भागने की असली वजह, उनका तानाशाहाना मिजाज है। नरेंद्र मोदी खुद को भारत का बादशाह या शहंशाह या चक्रवर्ती सम्राट जैसा कुछ समझते हैं, जिसकी इच्छा ही सर्वोपरि है और जिसका निर्णय ही कानून है। वास्तव में निर्वाचित सत्ताधारा के सर्वोपरि होने की दलील, मोदी राज में सत्ता के प्रधान नैरेटिव के रूप में बार-बार हमें सुनने को मिलती है। यही दलील जरा तिर्यक रूप से खुद प्रधानमंत्री मोदी के दावों में भी हमें सुनने को मिलती है, जब वह 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बोलने का दावा ही नहीं करते हैं, यह दावा भी करते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि की उनकी हैसियत, उनकी तमाम आलोचनाओं को, उन के खिलाफ तमाम आरोपों को, खारिज कर देती है। नरेंद्र मोदी के शब्दों में, 140 करोड़ भारतीय उनकी ढाल बन जाते हैं। इसी तानाशाहाना मिजाज का नतीजा है कि मोदी राज के दस साल में खुद संसद समेत, जनतंत्र की सभी संस्थाओं को कमजोर किया गया है, उनकी स्वतंत्रता को खत्म किया गया है। खुद कार्यपालिका तक में सारी की सारी शक्ति को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रित किया गया है। संसद की कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने की भूमिका को लगभग खत्म ही कर दिया गया है। न्यायपालिका को पालतू बनाने की कोशिशों के अलावा, उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कायम करने के लिए, मोदी राज ने बराबर एक जंग सी ही छेड़े रखी है। मुख्यधारा के मीडिया पर सत्ताधारियों द्वारा करीब-करीब पूरा कब्जा ही किया जा चुका है। ऐसा ही हाल उच्च शिक्षा संस्थानों का है और जेएनयू आदि की तरह जिन इका-दुका संस्थाओं ने अपवादस्वरूप अपनी स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए संघर्ष जारी रखा है, उन्हें शासन द्वारा एक प्रकार से शत्रु-संस्थाएं ही घोषित कर दिया गया है, जिन्हें जीतने की उसकी जंग लगातार जारी रही है। सीबीआई, ईडी, एनआईए आदि व पुलिस बलों, सभी संस्थाओं को सत्ताधारियों के ही नहीं, उनमें भी सबसे बड़कर बादशाह सलामत और उनके दरबार के औजारों में बदल दिया गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि ये बदलाव, वर्तमान सत्ता के तकाजों के अनुरूप हैं जरूर, लेकिन तात्कालिक तकाजों के ही सीमित नहीं हैं। वे पूरी राज्य व्यवस्था को ही तानाशाही में तब्दील कर रहे हैं। और तो और बहुसंख्यक धार्मिक प्रतिष्ठान को भी महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया है। एक ओर राम मंदिर और दूसरी ओर संगोल जैसे टोटकों के सहारे, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को धार्मिक अनुमोदन-प्राप्त महाराजक के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके आगे धार्मिक सत्ता भी व्यवहारतः नतमस्तक है। और दूसरी ओर, इससे भी महत्वपूर्ण रूप से बहुसंख्यक धार्मिकता को, अल्पसंख्यक विरोधी सांप्रदायिकता से खुद को परिभाषित करने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा दिया गया है। इसी का नतीजा हम चुनाव की हाथ से निकलती नजर आती बाजी को बचाने के लिए, अंतिम और इकलौते उपाय के रूप में, मोदी की भाषणा द्वारा चुनाव प्रचार में लौट-लौटकर, मुस्लिमविरोधी सांप्रदायिकता का सहारा लिए जाने के रूप में देख रहे हैं। यह बेतब होते हुए भी काम से कम हैरान नहीं करता है कि चौथे चरण के मतदान के दिन, गंगा के तट पर एक और छद्म साक्षात्कार में मोदी जी ने अचानक यह ऐलान कर दिया कि वह हिंदू-मुस्लिम नहीं करते हैं, वह हिंदू-मुस्लिम करें तब तो वह सार्वजनिक राजनीति के लायक ही नहीं रहेंगे और यह भी कि उनका संकल्प है कि वह हिंदू-मुस्लिम नहीं करेंगे। और चौबीस घंटे भी पूरे होने से पहले-पहले, अगले दिन महाराष्ट्र में वह हिंदू-मुस्लिम करने से भी आगे, इस्का ऐलान करने तक छेले गए कि उनके विरोधी जीत गए, तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवा देंगे। बाद में उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों से राम मंदिर पर बुलडोजर ही चलवा दिया! बेशक, यह हार की बदसवासी का संकेत है, लेकिन यह इसका भी संकेत है कि तानाशाह के पास यही एक चाल बची है, जिसे वह रह-रहकर आजमा रहा है।

## एक नजर

इस बार देश में बदलाव की हवा चल रही है: शशि थरूर



पटना, एजेंसी। कांग्रेस के निवर्तमान सांसद एवं वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने दावा किया है कि इस बार देश में बदलाव की हवा चल रही है। चार जून को जब लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा तब पता चल जाएगा। पटना के सदाकत आश्रम में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए ये दावा किया। शशि थरूर ने कहा कि पांचवें चरण के चुनाव के बाद भाजपा बहुमत के निशान से काफी नीचे चली जाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान के बाद देशभर में विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन के लिए रुझान बेहद उत्साहजनक हैं। कांग्रेस सांसद थरूर ने दावा किया कि चार जून को मतगणना के दिन केंद्र में सरकार बदल जाएगी। चार जून को दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का विश्वास जताते हुए कहा कि इस समय सरकार में भाजपा के पास लोकसभा में 303 का बहुमत है लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि वे सत्ता से जा रहे हैं। बहुमत के आंकड़े से भाजपा काफी नीचे है। उनका मौजूदा गठबंधन एनडीए भी उन्हें बहुमत तक पहुंचने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। थरूर ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन के लिए रुझान किसी एक एरिया में नहीं है बल्कि भारत के हर जगह में है। हम अपने उम्मीदवारों के प्रति उल्लेखनीय उत्साह और भाजपा के प्रति उत्साह की उल्लेखनीय कमी देख रहे हैं। कई मामलों में भाजपा के गढ़ों में, मतदान में गिरावट आई है।

### वाल्मीकी नगर में आपातकालीन स्थिति के लिए एयर एम्बुलेंस का सेवा उपलब्ध



पश्चिम चंपारण (बगहा)। विशेष सचिव सह अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के ज्ञांक 2606 के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के छठे चरण के मतदान में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटने हेतु 24 मई से 26 मई तक वाल्मीकी नगर स्थित हवाई अड्डा में एयर एम्बुलेंस का ठहराव सुनिश्चित किया गया है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण के कार्यालय के ज्ञांक 1068 के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनाटांड को एयर एम्बुलेंस के ठहराव स्थल पर मेडिकल टीम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ठहराव स्थल पर सभी आवश्यक दवाएं, उपकरण और पारा मेडिकल टीम और चिकित्सक की टीम को उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है। इस सन्दर्भ में पूछे जाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हनाटांड के राजेश सिंह नीरज ने बताया कि इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के दिशा-निर्देश पर वाल्मीकी नगर लोकसभा के वाल्मीकी नगर में एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है। ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में पीड़ित को त्वरित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके।

### डीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

सहरसा। जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 ई एवं 107 के निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। एनएच 107 के निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति के संबंध में बताया गया कि मौजा पहाडपुर में अतिक्रमण को दूर कर कार्य प्रारंभ कर डीबीएम कार्य पूर्ण कर दिया गया है। बेंजनाथपुर चौक के समीप कुछ स्थाई संरचना जिसके कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है, को कार्यरित में हटाया जाना अति आवश्यक है। डीएम ने निर्देश दिया कि अंचलाधिकारी सौर बाजार एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाते हुए यथोचित कारवाई की जाय। फ्लाइंग आपूर्ति के संबंध में जानकारी दी गई कि एनटीपीसी द्वारा ट्रांसपोर्टर को आपूर्ति हेतु ऑर्डर कर दिया गया है। जून के प्रथम सप्ताह से फ्लाइंग को आपूर्ति संभावित है। मेजर ब्रिज एवं मनौरी भीयूपी पहुंचपथ के निर्माण के संबंध में बताया गया कि उक्त वर्णित दोनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बॉक्स कलभट्ट निर्माण की वर्तमान प्रगति के संबंध में बताया गया कि 71 में 61 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 10 में से 02 में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

### सात दिनों के बाद एमपी ने लिया पीड़ित परिजनों का हाल, दोषी पर कार्रवाई की कही बात

अररिया। अररिया के निवर्तमान एमपी प्रदीप कुमार सिंह शुक्रवार को ताराबाड़ी पहुंचे। ताराबाड़ी के पटेगना स्थित मायके में एमपी प्रदीप कुमार सिंह ने मृतक मिट्टू की पत्नी मुस्काण सहित उनके परिजनों से मुलाकात की और घटना को लेकर जानकारी ली। एमपी ने पीड़ित परिजनों को आशस्त किया कि मामले की न्यायिक जांच की जायेगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताराबाड़ी थाना में पिछले सप्ताह जीजा साली के खुदकुशी के बाद जमकर उद्रव हुआ था। आक्रोशित लोगों ने थाना में पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। जिससे सदर एसडीपीओ सहित कई पुलिसकर्मी के साथ स्थानीय ग्रामीण भी घायल हुए थे। मामले में डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जिसके बाद से पूरे इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया था। घटना के बाद से ही एमपी प्रदीप कुमार सिंह अलग अलग स्थानों पर हो रहे चुनाव को लेकर कैंपेन में थे। जहां से आज शुक्रवार को अररिया लौटते ही सबसे पहले ताराबाड़ी पहुंचे और पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की।

## हृदय रोग से पीड़ित दिलनवाज एवं रियाज को सफल इलाज के लिए भेजा गया अहमदाबाद



किशनगंज, एजेंसी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) बच्चों को सुविधाजनक तरीके से समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल है। इसी क्रम में जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित जिले के कोचामामन प्रखंड के 13 वर्षीय दिलनवाज आलम एवं 11 वर्षीय रियाज आलम को सफल इलाज के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल से एम्बुलेंस के द्वारा पटना तथा शुक्रवार को पटना से हवाई जहाज से अहमदाबाद भेजा गया है। शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि जिले में हृदय में छेद के साथ जन्में कई बच्चों की मुफ्त सफल सर्जरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आरबीएसके में शामिल मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत जिले में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का समुचित

इलाज हो रहा व पीड़ित बच्चे स्वस्थ भी हो रहे हैं। जो आरबीएसके टीम की सकारात्मक पहल का परिणाम है। इसके लिए जिले में पीएचसी से लेकर जिला स्तर के अस्पतालों में तैनात आरबीएसके टीम क्षेत्र भ्रमण कर ऐसे बच्चों को ना सिर्फ चिह्नित कर रही बल्कि, उनका निःशुल्क समुचित इलाज भी सुनिश्चित करवा रही है। ताकि पीड़ित बच्चों को सुविधाजनक तरीके से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ मिल सके। आरबीएसके डीआईसी प्रबंधक सह जिला समन्वयक पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चों का इलाज सात निश्चय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत बिल्कुल मुफ्त होगा। इसमें मरीज बच्चा और उसके एक अभिभावक को सरकार अपने खर्च पर अहमदाबाद ले जाकर उचित इलाज करवाती है।

उनके मुताबिक दोनों बच्चों को जन्म से ही दिल में छेद था, जिसे उका सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा था। उसके पिता ने बताया कि बच्चों को बार बार बुखार तथा जल्द ही थकान होने लगती थी। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद इलाज के लिए जा रहे बच्चों की स्त्रीनिंग आईजीआईसी में हुई थी। जहां उनके दिल में छेद होने की पुष्टि हुई। इलाज के बाद इनका फॉलोअप भी किया जाएगा सिविल सर्जन डा. राजेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को किसी प्रकार की गंभीर समस्या होने पर आईजीआईएमएस, एम्स पटना व पीएमसीएच भेजा जाता है। उन्होंने बताया, जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में हमारी टीम तैनात है। जिसमें दो चिकित्सक, एक एएनएम और फार्मासिस्ट शामिल हैं।

## अपहरण, लूट, पलायन, नरसंहार का राज्य अब फिर से बिहार को नहीं बनने दिया जाएगा: नीतीश कुमार

पटना/रोहतास, एजेंसी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को काराकाट से राजग उम्मीदवार उषेंद्र कुशवाहा के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपहरण, लूट, पलायन, नरसंहार का राज्य अब फिर से बिहार को नहीं बनने दिया जाएगा। भाजपा के साथ मिलकर बिहार को बड़ी मुश्किल से पटरी पर लाये हैं। अब लोग बिना किसी भय के रात में भी घूमने निकलते हैं। हमने यहां कानून का राज स्थापित किया है। अब बिहार में कोई गलत काम करने वाला सिर उठा के नहीं चल सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने दो बार उन्हें (लालू परिवार) को मौका दिया लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। वे लोग हमेशा से बिहार को लूटने की मंशा पाले हुए हैं जिसके चलते हमने अपना रास्ता अलग कर लिया।



यादव) के पिता के शासन काल में यहां क्या था ? लोग उसे भूले नहीं हैं। अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार उषेंद्र कुशवाहा के गले में माला डालते हुए लोगों से हाथ उठाकर जीत दिलाने का भरोसा मांगा। नीतीश कुमार ने लालू-रावडी के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि उनके (तेजस्वी

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आप समर्थन करें। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी बोल पड़े, आप पीएम मोदी के लिए वोट करें। उनके नेतृत्व में देश तरकी कर रहा है। रल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां सहित मंच पर जितने भी नेता थे सभी ने मोदी का नाम लिया और उनके नेतृत्व में समर्थन की अपील की।

## अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध को अंजाम देने वाले तीन अपराधी गिरफ्तार

अररिया। भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध को अंजाम देने वाले तीन साइबर अपराधियों को अररिया जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के जोगबनी थाना क्षेत्र के टिकुलिया बस्ती वार्ड संख्या चार से की गई। गिरफ्तार किए गए तीन साइबर अपराधियों में एक भारतीय, जबकि दो नेपाली नागरिक शामिल हैं।

इन्होंने एनडीए उम्मीदवार उषेंद्र कुशवाहा के गले में माला डालते हुए लोगों से हाथ उठाकर जीत दिलाने का भरोसा मांगा। नीतीश कुमार ने लालू-रावडी के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि उनके (तेजस्वी

यह लोग सट्टा बाजार के लालच में फंसाने का काम करते थे। एस्पपी ने बताया कि रेटिना का फोटो खींच हेरफेर और आधार कार्ड में हेरफेर करके एक ही व्यक्ति के नाम पर अनेक मोबाइल सिम कार्ड को एक्टिवेट कर नेपाल में साइबर फ्रांइजम में इस्तेमाल किया जाता था।

इन साइबर अपराधियों का लक्ष्य प्रति माह 2 हजार सिम कार्ड का रहता है। छापेमारी में 114 सिमकार्ड बरामद किए गए। एस्पपी ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से लगातार साइबर अपराध को अंजाम देने की जानकारी मिल रही थी, जिसको लेकर कार्रवाई के लिए एनडीए उम्मीदवार उषेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जोगबनी थानाध्यक्ष राजीव कुमार आजाद, एसआई अंजू कुमारी, डीआईयू टीम एवं सशस्त्र पुलिस बल टीम के साथ टीम का गठन किया गया था। टीम ने जोगबनी टिकुलिया बस्ती इंदिरानगर वार्ड संख्या 4 में 28 वर्षीय मो. शमी अंसारी उर्फ साइबर अपराधी इंटरनेशनल लेवल पर साइबर क्राइम करते थे। मुख्य रूप से

## बकरी पालन गरीब एवं सीमांत किसानों के लिए एक उचित लाभ का व्यवसाय: डॉ एस कुंडू

समस्तीपुर। निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा कृषि विज्ञान केंद्र बिरोली के द्वारा आज चार दिवसीय व्यावसायिक बकरी पालन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुुरुआत की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले से युवा शामिल हुए हैं। इस मौके पर डॉ एस कुंडू ने कहा कि बकरी पालन गरीब एवं सीमांत किसानों के लिए एक उचित लाभ का व्यवसाय है।

कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर एम एस कुंडू सर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष कुमार पशु चिकित्सा पदाधिकारी ताजपुर डॉक्टर आरपी सिंह वरीय वैज्ञानिक सह प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज डॉक्टर आरके तिवारी कृषि विज्ञान केंद्र बिरोली सुश्री अभिलिप्सा बिस्वाल विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिरोली उपस्थित थे। अपने संबोधन में निदेशक प्रसार शिक्षा ने बकरी पालन किस प्रकार किया जाए। जिससे उनको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसके बारे में विस्तृत जानकारी सभी प्रशिक्षक साथियों को उपलब्ध कराया। साथ ही साथ उसका खानपान एवं विभिन्न प्रकार के नस्ल प्रबंधन पर मुख्य रूप से चर्चा की। पशु



बिचकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार ने बिहार सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। डॉ आर पी सिंह द्वारा बेतिया जिले में किस प्रकार बकरी पालन का कार्य किया जाता है। इसकी प्रयोग जानकारी सभी लोगों को उपलब्ध कराई। डॉ

आरके तिवारी प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बिरोली के द्वारा यह बताया गया की बकरी पालन गरीब किसानों के लिए एक बरदान है। उनके द्वारा बकरी पालन कर अपनी आजीविका में सुधार लाया जा सकता है। इसको अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो इससे हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

## मतगणना को लेकर मतगणना केंद्र की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश



पूर्णिया, एजेंसी। जैसे-जैसे मतगणना की तिथि 4 जून का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे-वैसे प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की गति भी तेज होती जा रही है। मतगणना स्थल पर हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, स्वास्थ्य प्रशिक्षण पार्किंग इत्यादि की तैयारियों पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार खुद नजर रख रहे हैं। मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्यालय वेशम में हुई लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मतगणना की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक में कई आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों से मतगणना की तैयारियों के संबंध में जानकारी मांगी। नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग सह वरीय उप समाहर्ता पूर्णिया के द्वारा बताया गया कि मतगणना हेतु कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु प्रथम नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया है तथा मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारित कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा मतगणना कर्मियों को सही प्रशिक्षण के साथ उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण की जांच करने का निर्देश दिया गया। नगर आयुक्त पूर्णिया पदाधिकारी पूर्णिया से मतगणना संबंधी सभी प्रपत्रों को समयतय तैयार रखने का निर्देश दिया गया। आईटी मैनेजर पूर्णिया को मतगणना के समय सभी प्रतिवेदन के ऑनलाइन अपलोड करने हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तथा आवश्यक तैयारियों को समय पूर्व पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। नगर आयुक्त पूर्णिया को मतगणना केंद्र पर साफ सफाई तथा पेयजल की उपलब्धता, गर्मी के आलोक में मतगणना केंद्र पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, मतगणना केंद्र पर बैरिकेटिंग करने तथा प्रयास संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का भी आवश्यक निर्देश दिया गया। इस बैठक में जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को कहा गया कि निर्वाचन के आखरी चरण में सभी को एक साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना है जिससे निर्वाचन सफलता पूर्वक संपन्न कराया जा सके।

## किशनगंज पुलिस पर पश्चिम बंगाल में हमला, थानेदार ने की पांच राउंड फायरिंग, 2 सिपाही घायल

किशनगंज। बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे किशनगंज शहर से सटे पश्चिम बंगाल के विलायतीवारी में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची बिहार पुलिस की टीम को उग्र भीड़ ने घेर लिया और उनपर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए किशनगंज सदर थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बीच बचाव में पांच राउंड फायरिंग की। गोली लगने से दो लोग घायल हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण और भी उग्र हो गए। भीड़ ने सदर थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। सदर थाना पुलिस ट्रैक्टर और मकई की लूट कांड मामले में यहां एक युवक को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान सदर थानाध्यक्ष संदीप कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीणों ने यहां पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद जान बचाने के लिए सदर थानाध्यक्ष संदीप कुमार को पांच राउंड फायरिंग करनी पड़ी।

फायरिंग की आवाज सुनकर आक्रोशित भीड़ ने थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में दो सिपाही सहित कई ग्रामीण घायल हो गए। हमले में दो ग्रामीणों को गोली लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि, सदर थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने एक आरोपी अब्दुल तउब के बेटे नूर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, दोनों घायल युवक को चर्कलिया अस्पताल ले जाया गया है। यहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मदद नहीं ली। मामले में दालकोला एसडीपीओ रतिन नाथ विश्वास ने बताया कि हम लोग को सूचना मिली



थी कि चार-पांच बिहार के पुलिसकर्मी बंगाल के एक लड़के को पकड़ने आए हैं। लेकिन, बिहार पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बंगाल पुलिस की मदद नहीं ली। उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ है। बंगाल पुलिस की ओर से कहा गया है कि उन्हें बिहार पुलिस की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई और फायरिंग की गई है। स्थानीय विधायक मिनाज आलम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने बिना बंगाल पुलिस को जानकारी दिए यहां रेड की। एक स्थानीय नूर आलम को पकड़कर ले गए। उसका क्या कसूर है, पता नहीं है। उन्होंने फायरिंग भी की, जिसमें 2-3 लोग घायल हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है। यहां की पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। मिनाज आलम ने आगे कहा कि हमलोग बिहार-बंगाल के बोर्डर पर रहते हैं। हमें शांतिपूर्वक रहना होगा। लेकिन, बिहार की पुलिस का यह काम तानाशाही वाला है। हम इसके खिलाफ डीएम-एसपी से शिकायत करेंगे। आगे सरकार से भी बात करेंगे।





एक नजर

**फिया ग्लोबल के ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ के पार: कंपनी**

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत और नेपाल में ऐप आधारित सूक्ष्म ऋण सुविधा देने वाली फिनटेक कंपनी फिया ग्लोबल ने शुक्रवार को कहा कि उसके ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ के ऊपर पहुंच गयी। डिजिटल एप फिनवेस्टा के माध्यम से सेवा दे रही कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसके ऐप के माध्यम से 155 करोड़ रुपये प्रतिदिन से अधिक लेनदेन हो रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी के ग्राहकों में एक करोड़ से ज्यादा महिला ग्राहक हैं तथा उसका ग्राहकों का आधार 45 हजार गांवों और 4600 नगरों में फैला है। फिया ग्लोबल की सह-संस्थापक और मुख्य अधिशासी सीमा प्रेम ने कहा, हमें प्रसन्नता है कि हमने 10 करोड़ लोगों और सूक्ष्म उद्यमों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है जिससे उन्हें अब महंगी दरों पर कर्ज देने वाले स्रोतों पर निर्भर नहीं करना पड़ता। हमारा उद्देश्य नगद के डिजिटलीकरण से आगे जाना और आय पैदा करने के अवसर उपलब्ध कराकर स्थायी वित्तीय कल्याण करना है। फिया कर्मजोर आय वर्ग के लोगों के लिए डिजिटल भुगतान, ऋण और संहार, बीमा और वेलथ मैनेजमेंट जैसी सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी देश में विकसित बीटूबी डिजिटल एप फिनवेस्टा और बैंकिंग प्रतिनिधियों आदि के जरिए काम करती है। फिया ग्लोबल ने कहा है कि उसके ऐप के जरिए ग्राहकों के बैंक खातों में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर्ज सहायता पहुंची है और इससे आजीविका के स्थायी स्रोतों का निर्माण हो रहा है। कंपनी के ग्राहकों में सूक्ष्म उद्यम भी शामिल हैं और 20 लाख से ज्यादा ने जनधन योजना और अटल पेंशन योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकरण कराया है।

**जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम को मिली राहत, सात साल की सजा पर लगी रोक**

**प्रयागराज।** उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है। न्यायालय ने आजम खान को बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उन्हें राहत दी है। उनके खिलाफ सुनाए गए सात साल की कैद के सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि, पत्नी तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को इस केस में राहत नहीं मिल पाई है। आजम परिवार ने इस केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सजा को चुनौती दी थी। दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली सात साल की सजा के खिलाफ याचिकाओं के बाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। आजम खान, अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फात्मा को रामपुर की स्पेशल कोर्ट से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में सात साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में आजम खान, पत्नी और बेटे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान को राहत दी है। उनकी सजा पर रोक लगा दी है। उन्हें जमानत भी दे दी है। जमानत मिलने के बाद आजम खान का परिवार जेल से बाहर आ सकता है। आजम के साथ-साथ पत्नी और बेटे को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। रामपुर की विशेष अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात साल की सजा सुनाई थी। उन पर 50-50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया था। उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।

**बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुका है एनडीए: मानु वर्मा**

**देवरिया।** केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दावा किया कि पांच चरणों के मतदान के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) बहुमत के आंकड़ों से काफी आगे निकल चुका है। श्री वर्मा ने कहा कि आज देश में मोदी के नाम की लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही है। पांच चरणों के मतदान के बाद जो अपडेट मिल रहे हैं। उसके अनुसार एनडीए गठबन्धन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से आगे निकल चुकी है। आगे के दो चरणों में पार्टी का आंकड़ा 400 पार कर जायेगा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबन्धन एक भी सीट नहीं पा रही है, जनता इनको पूरी तरह नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित भारत बनाने, समृद्ध भारत बनाने, सशक्त भारत बनाने और विश्वरूप भारत बनाने के लिये देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को, भाजपा को, एनडीए गठबंधन को दलित खोलकर वोट कर रही है। इससे इंडी गठबंधन के नेताओं के होश उड़ें हैं और वे अनाप-सनाप बातें कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

**केन्द्र ईएसी की बैठक में केरल के नए मुख्य पेरियार बांध के प्रस्ताव को हटाए: स्टालिन**

**चेन्नई, एजेंसी।** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर मुख्य पेरियार में नया बांध बनाने के केरल सरकार के कदम पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए शुक्रवार शाम केंद्र से विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की आगामी 28 मई की बैठक के एजेंडा में शामिल केरल के इस प्रस्ताव को हटा देने का आग्रह किया। श्री स्टालिन ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव को एक अर्ध-सरकारी पत्र में कहा कि केरल में मौजूदा मुख्य पेरियार बांध के बदले में एक नए बांध के निर्माण का प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ है और विशेषज्ञ समितियों द्वारा भी बार-बार पाया गया है बांध हर तरह से सुरक्षित है। यह अदालत की अवमानना है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो तमिलनाडु सरकार केरल को भविष्य में ऐसे किसी भी प्रस्ताव को लाने से रोकने के लिए अवमानना कार्रवाई शुरू करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। श्री स्टालिन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए मुख्य पेरियार में एक नए बांध के निर्माण के लिए अध्ययन करने के केरल के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के विचार पर तमिलनाडु सरकार की कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा, हमें

निर्देशों के खिलाफ है। मौजूदा बांध को विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा बार-बार सभी पहलुओं में सुरक्षित पाया गया है और उच्चतम न्यायालय ने 27 फरवरी, 2006 और सात मई, 2014 के अपने फैसलों में यह बात कही है। उन्होंने दोहराया बाद में 2018 में जब केरल ने एक नए बांध के प्रस्ताव के लिए ईआईए अध्ययन के लिए टीओआर की मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास किया तो इस मुद्दे को तमिलनाडु ने उच्चतम न्यायालय में उठवाया और यह स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया गया कि ऐसा कोई भी इस कदम के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होगी। श्री स्टालिन ने कहा, इस मुद्दे पर हमारी आपत्तियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा सचिव, एमओईएफ और ईएसी के सभी सदस्यों को पहले ही विस्तार से बता दिया गया है। मुख्यमंत्री ने श्री भूपेन्द्र यादव से आग्रह किया कि वे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों और ईएसी के सदस्य सचिव को 28 मई को होने वाली ईएसी बैठक के दौरान नए बांध के लिए प्रस्तावित ईआईए पर एजेंडा आइटम को हटाने का निर्देश दें और ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर भविष्य में विचार न करें। उन्होंने कहा, स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मैं इस संबंध में आपके तत्काल व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूँ।

**अधिकारियों ने मीरवाइज को जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका: अंजुमन**



**श्रीनगर।** जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कान्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं कश्मीर के प्रमुख मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को अधिकारियों ने लगातार चौथे शुक्रवार को श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में धर्मोपदेश देने और नमाज अदा करने से रोका। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने यह जानकारी दी है। जामिया मस्जिद के प्रबंध निकाय ने कहा कि मौलवी मीरवाइज को गत तीन मई से शुक्रवार की नमाज अदा करने से रोका गया है। अंजुमन ने गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मौलवी मीरवाइज को

**मजनलाल सरकार मीषण गर्मी एवं लू से आमजन को राहत प्रदान करने के लिए पूरी एक्शन मोड में आ रही है नजर**

**जयपुर, एजेंसी।** राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लगातार मॉनिटरिंग में राज्य सरकार वर्तमान में जारी प्रचंड गर्मी एवं लू से आमजन को राहत प्रदान करने के लिए पूरी एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजधानी जयपुर से लेकर जिलों तक आमजन को पर्याप्त बिजली और पानी उपलब्ध कराने से लेकर गर्मी और लू-जनित बीमारियों से राहत दिलाने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी कंठिजेसी प्लान को अमल में लाने लिए फोल्ड में डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गर्मी की मार से गोवंश और पशुधन को राहत प्रदान करने के लिए भी माकूल प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को भी मुख्य सचिव सुधांशु पंत से बात कर निर्देश दिए कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सभी डिस्कॉम सहित पशुपालन और गोपालन विभागों में निरंतर मॉनिटरिंग रखते हुए सक्रियता से कार्य किया जाए और तत्काल कार्यवाही करते हुए राहत प्रदान की जाए। उन्होंने प्रदेश में आमजन से लेकर पशुधन को गर्मी से राहत दिलाने के लिए सभी विभागों को उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिये। श्री शर्मा ने कहा कि प्राथमिकता से भीषण गर्मी और लू-प्रकोप संबंधी प्रबंधन कार्यों को समय से पूरा करें एवं इनकी निरंतर समीक्षा भी करें। श्री शर्मा ने प्रचण्ड गर्मी के हालात के मद्देनजर आमजन से अपील की है कि लू के प्रकोप से बचने के लिए विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग दोपहर में बाहर निकलने से परहेज करें। लू से बचाव

**हिमाचल में एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में कटौती की तैयारी: अनुराग**

**कुटलैहड़/नैनादेवी, एजेंसी।** केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने अस्तित्व से लेकर आज तक अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विरोधी रही है वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदा ही एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के उत्थान के लिए कार्य करती आई है। श्री ठाकुर ने यह बातें कुटलैहड़ और श्री नैना देवी विधानसभा में अपने दर्जन भर से अधिक कार्यक्रमों और जनसभाओं के दौरान कहीं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और पिछड़ी पार्टियों को सेना और एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के मुद्दों पर भी जमकर धेरा। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस ही है जिसने भारत में को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने कि बीमारी शुरू की है। जहां भी इनकी राज्य सरकारें आती हैं वहां यह लोग एससी, एसटी और ओबीसी भाइयों-बहनों का आरक्षण छीन कर तुष्टिकरण के लिए अपने वोट बैंक को दे देते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों को क्यों नहीं बताते की क्या हिमाचल में भी वो एससी-एसटी और ओबीसी समुदाय का आरक्षण में कटौती की तैयारी में हैं या नहीं। राज्य के हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार ठाकुर ने आगे बताया कि पिछले 10 वर्षों में वंचित हीं मोदी सरकार की वरीयता में रहे हैं। एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय का जो विकास मोदी जी ने किया है वह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। हमारे एससी, एसटी और ओबीसी भाई बहन आज खुल कल भाजपा के पक्ष में आ गए हैं। हमीरपुर समेत संपूर्ण हिमाचल में प्रतिदिन सैकड़ों एससी, एसटी और ओबीसी परिवार भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार कि जनकल्याणकारी



योजनाओं का अधिकतम लाभ इन्हीं को मिला है। श्री ठाकुर ने आगे कहा, “कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एससी समाज कल्याण के लिए प्रतिवर्ष मात्र 40 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया जाता था। आज, भाजपा सरकार में एससी समुदाय के कल्याण का बजट 1 लाख 40 हजार करोड़ से अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, सामाजिक न्याय मंत्रालय के बजट में अनुसूचित जातियों पर विशेष ध्यान देने के साथ 90 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई है। आज कांग्रेस वाले अपनी स्पष्ट हार को देखते हुए संविधान का नाम लेकर झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है की कांग्रेस ने हमेशा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को कम करके आंका है। कांग्रेस ने तो संविधान सभा के लिए बीआर अंबेडकर के चुनाव का भी विरोध किया था। जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया, लेकिन बीआर अंबेडकर जी को उनके निधन के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, “बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न से तब सम्मानित किया

**प्रधानमंत्री बताएं, आपदा में हिमाचल को कहां धन दिया: सुक्खू खड़ा चरण में झारखंड के सभी 8963 बूथों पर वेब कारिंटग से रखी जाएगी नजर: के. रवि कुमार**



**हमीरपुर, एजेंसी।** हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कहां धन दिया। आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री को हिमाचल दौरे पर बात करनी चाहिए थी। हिमाचल को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ का पैसा मिला है, जो आपदा आये या न आए मिलता ही है। प्रदेश सरकार ने 9900 करोड़ रुपये का संशोधित दावा नोट केंद्र सरकार को भेजा था, उसमें से भी कोई राशि नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी नेता झूठ बोलना छोड़कर यह बताना शुरू करें कि कितनी विशेष राहत राशि हिमाचल को केंद्र ने दी है।



मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नानन व मंडी में दिए जुमलेबाज भाषण पर यह जवाब सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कोट, चौरी व टीणीदेवी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिले। उन्हें शायद विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने गलत जानकारी दे दी। प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लाहौल स्पीति में महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो गई है। 1150 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही 2.37 लाख महिलाओं को भी 1500 रुपये खाते में आना शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री को जयराम ठाकुर को पूछना चाहिए कि वह 1500 रुपये रकवाने चुनाव आयोग में क्यों गए। अगर भाजपा आज चुनाव आयोग में लिखकर दे कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फार्म भर चुकी महिलाओं के

खते में कुल 1500 रुपये आ जाएंगे। श्री सुक्खू ने कहा कि 1500 रुपये की गारंटी कांग्रेस की है, यह राशि महिलाओं को 4 जून के बाद मिल ही जाएगी। भाजपा व जयराम ठाकुर जितनी मर्जी ताकत लगा लें महिलाओं के पैसे नहीं रोक पाएंगे। भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को राजनीतिक मंडी में खरीदने के लिए पैसा लगाया, आपदा में देने के लिए उनके पास राशि नहीं थी। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र बिके भी आपदा में नहीं दिखे। मैंने खुद दौरा किया तब चंडीगढ़ से आए। राजेंद्र बिके सुजानपुर की जनता की खनिज संपदा खुड़ों से लूट रहे हैं। उनके कई ऊंशर पार्टनरशिप में हैं, वह अपने काम करवाने ही आते थे जनता के काम कभी नहीं लाये। सुजानपुर का विकास कांग्रेस की देन

है। राजेंद्र अब बिके ही रहेंगे, जनता की अदालत में टिकेंगे नहीं। वह जनता को जितने भी प्रलोभन दे लें, कोई चक्कर में आने वाला नहीं है। उन्होंने सुजानपुर की जनता के साथ धोखा किया है। उन्हें हमीरपुर जिला का विधायक रास नहीं आया, वह अपने मंत्री पद के लिए इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि भाजपा की राजनीतिक मंडी में बिक गए। राज्यसभा चुनाव से पहले फेस जुस हमारे साथ पिया, अभिषेक मनु सिंघवी को जिताने की कसमें खाते रहे, लेकिन मुझे क्या पता था पहले ही खुद को बेच चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर को भी आजकल झूठ बोलने की आदत लग गई है। वह हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर लगातार झूठ बोल



रहे हैं। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज 3 मार्च 2014 को मंजूर हुआ था, 2015 में नहीं। श्री अनुराग झूठ बोलने की हद पार कर चुके हैं, उन्हें सच का ज्ञान नहीं। अगर मेडिकल कॉलेज भाजपा लाई होती तो उसका नामकरण डॉ राधाकृष्णन नहीं दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर होता। चंबा मेडिकल कॉलेज जवाहरलाल नेहरू व नाहन मेडिकल कॉलेज यशवंत परमार जी के नाम पर है, क्योंकि यह कांग्रेस की देन है। भाजपा लाई होती तो अपने नेताओं के नाम पर नामकरण करती। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर में लड़ाई ईमानदार व बेईमान के बीच है। कांग्रेस ने कैंपटन रणजीत को ईमानदारी पर टिकट दिया है, सुजानपुर की जनता उनका साथ दे, क्षेत्र में पानी, बेसहारा पशुओं सहित सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं भी आपका विधायक बनकर ही काम करूंगा। लोकसभा के लिए सतपाल रायजादा को वोट दें। छब्बीस साल से भाजपा सांसद हमीरपुर सीट से बन रहा है, लेकिन काम कोई नहीं किया। ट्रेन हमीरपुर पहुंच गई और सीटी मारती हुई जा रही है, अनुराग ने रेलवे लाइन के मुद्दे पर भी हमेशा लोगों को ठगा है। अब वह कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार पैसे नहीं दे रही। इस दौरान लोकसभा उम्मीदवार सतपाल राजजादा, विधानसभा उम्मीदवार कैप्टन रणजीत, विधायक चंद्रशेखर, पूर्व सीपीएस अनोता वर्मा, कैथेसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पटानिया, जिला अध्यक्ष सुमन भारती, विशेष पयंवेक्षक संदीप, अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर इत्यादि मौजूद थे।